औसतन एक मनुष्य की बलि लेता है गडकरी का फरीदाबाद राजमार्ग

रफ्तार के लिए बिके लूट के टोल प्लाजा, जनता मरे या भाड़ में जा

फ़रीदाबाद स्पीड हाई वे से विवेक की विशेष रपट

दिन रविवार का, समय रात के 8.30 बजे, मेवला महाराजपुर मेट्रो स्टेशन के सामने हाईवे पर एक 35 वर्षीय व्यक्ति का शरीर खून से लथपथ बीच सड़क पर पड़ा हुआ था। कारण था, सड़क पार करते हुए किसी तेज रफ्तार मोटर का टक्कर मारना। सैकड़ों लोगों का हूजूम देख रहा था और हर गाड़ी वाला स्पीड कम करते हुए बगल से निकलता रहा। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो गाड़ी रोक कर चोटिल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाये।

मैने अपनी कार एक किनारे रोक कर दसियों बार पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन लगाया। जिस पर पुलिस की सहायता करने के लिए 1 नंबर बटन दबाने के निर्देश के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस कंट्रोल रूम से बाद में पूछने पर पता चला कि कंप्यूटर में कुछ न कुछ खराबी रहने के कारण ऐसा अक्सर हो जाता है।

बदरपुर टोल प्लाजा वालों से सहायता करने को कहने पर जवाब मिला कि वह इलाका पलवल टोल वालों का है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जबकि बदरपुर टोल प्लाजा से दुर्घटना स्थल की दूरी बमुश्किल एक किलोमीटर होगी। अंत में एक ऑटो रिक्शा वाला उस अचेत घायल को अस्पताल ले गया। उस व्यक्ति के घाव बता रहे थे कि वो बच नहीं सका होगा। शहर के बीच से गुजरते इस हाई वे का यह रोज का किस्सा है। एक मौत प्रतिदिन का औसत।

हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से किया। इस सड़क पर छायंसा के पास एक ही परिवार के 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। जिसका कारण था सड़क पर रोशनी का अभाव जो उद्घाटन के चक्कर में भूले बैठा रहा प्रशासन। कुछ दिन पहले दो इंजीनियर एक डम्पर से कुचल कर मारे गए थे। इसी तरह यमुना एक्सप्रेस वे और देश के कोने कोने से आये दिन लोगों के सड़क दुर्घटना में मारे जाने की खबरें आम हो चली हैं। हालिया नासिक में सड़क पर दस अकाल मौतों जैसी खबर हम अखबार में पढ़ते हैं और भूल जाते हैं।

केंद्र में सड़क व परिवहन मंत्रालय के मुखिया नितिन गडकरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में हर साल 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 1.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इन दुर्घटनाओं को कम करने का भरसक प्रयास करने के वादे के साथ उनकी वार्ता समाप्त हुई। ये वादा दोहराना गडकरी जी को तब याद आया जब सरकार सत्ता में अगले चुनाव से पहले अपने अंतिम दिन गिन रही है। खैर सरकारों के जनता से किये वादे तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, तब कर लो चाहे अब।

दरअसल सिर्फ रफ्तार वाली गाड़ियों और सत्ताधारियों की जेब कमाई को ही ध्यान में रख कर बनाये गए ये हाईवे आम आदमी के लिए जान का जोखिम हैं। बदरपुर टोल से एस्कॉर्ट मुजेसर तक बने पूरे हाईवे पर पैदल पार करने वालों के लिए मेट्रो स्टेशन की सीढियाँ ही हैं केवल। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी इतनी ज्यादा है कि कोई भी व्यक्ति इतना लम्बा चल कर जाने की बजाय तेज हाईवे के बीच से सड़क पार करना ज्यादा आसान समझता है। इस नजरिए को और मजबूती सड़क के बीच डिवाईडर रोक न होने से मिलती है। यानी एक ओर से दूसरी ओर जाया तो जा सकता है पर तेज रफ्तार गाड़ी से जान जाने का जोखिम उठा कर ही।

स्मार्ट सिटी की तेज रफ्तार सड़कों पर पैदल और साइकिल चालक के लिए कोई जगह नहीं। तेज रफ्तार वाहनों से बच-बच कर जाना इनकी नियति बन गई है। ऐसे में दुर्घटना का होना स्वाभाविक है। सेक्टर 31 के थाने की मानें तो इस हाईवे पर औसतन एक मौत रोज होती है। तो क्या कारण हैं कि नितिन गडकरी और अन्य मंत्रियों को ये मौतें सिर्फ आंकड़ों के रूप में ही याद आती हैं? तेज रफ्तार इन सड़कों का मकसद सत्ताधारियों के लिए सिर्फ अपनी जेबें भरना है।

टोल रोड बनने से पहले ही ठेकेदार कंपनियां इन पर टोल वसूलने लगती हैं। ज्यादातर मामलों में हाईवे का टेंडर कई टुकड़ों में अलग अलग नाम की कम्पनियों को दिया जाता है ताकि हर कंपनी का स्ट्रेच पूरा होते ही टोल वसूला जाने लगे।

बाकी का काम लूटखोरों की सुविधानुसार वर्षों चलता रहता है। सच्चाई ये है कि इन सभी कंपनियों का स्रोत एक ही होता है। फरीदाबाद के इस हाई वे को लेकर अम्बानी और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा की ऐसी ही मिलीभगत वाली लूट किसी से छिपी नहीं है, न अब खट्टर सरकार की उसी अंदाज में कार्यशैली।

अमूमन हाईवे पर पैदल क्रासिंग के लिए सीढियां तक नहीं दी जाती, एस्कैलेटर का तो सवाल ही नहीं उठता। कुछ एक स्थानों पर अंडर पास की व्यवस्था है परंतु वो भी सिर्फ मोटर वाहनों को ध्यान में रख कर इतने दूर दूर बनाये जाते हैं कि पैदल व्यक्ति चल कर जा न सके। जहाँ सीढ़ियाँ हैं भी वहाँ सिर्फ स्वस्थ युवाओं का ध्यान रखा गया है; विकलांग, बुजुर्ग, सामान से लदे व्यक्ति, महिला, बच्चों के लिए हर 500 मीटर पर लिफ्ट या स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था लाखों करोड़ से बन रहे राज मार्गों पर सरकार के लिए गैर जरूरी खर्च है। जनता है, मरने दो! डिवाईडरों से रिफ्लेक्टर गायब हैं और साइन बोर्ड लगाने की जहमत हाई वे के ठेकेदार उठाते ही नहीं। क्योंकि सरकार का रुझान रफ्तार और वसूली पर ही है

सिर्फ, आम नागरिक की सुरक्षा और सहूलियत सरकार के लिए मायने नहीं रखती। मायने रखता है तो ये कि प्रधानमंत्री के रोड शो में कितने लोग खड़े थे? मंत्री कृष्णपाल गूजर जो चुनाव से पहले इस वादे का हुक्का भरते रहे कि बदरपुर टोल हटवा देंगे क्योंकि ये जनता के पैसों की लूट है। अब ये कह कर साफ मुकर गए कि पिछली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो अब ये टोल नहीं हट सकता।

गुर्जर साहब मजबूर हैं, वो नहीं बता सकते कि पिछली सरकार खाती रही और अब हमारे खाने कि बारी है तो कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लूँ? फरीदाबाद से सटे पृथला पर एक नया टोल बना कर लूटने के उपक्रम जारी हैं।

जनता के लाख विरोध के बावजूद ये हो कर रहेगा पर कम से कम राहगीरों की सुरक्षा और सुविधा को तो सुनिश्चित किया जाए। चुनावी वादों और रोड शो के भ्रामक प्रचारों में जनता से जुड़े असली मुद्दे नारों के बीच दब जाते हैं जिसकी शक्ल सड़क पर पड़ी लाश के रूप में आये दिन सामने आती है।

अमूमन हम भी सरकारों कि तरह इन लाशों से किनारा काट कर निकल जाते हैं पर एक दिन हमारे किसी अपने की लाश भी इस सड़क पर हो सकती है। उस दिन किनारा करना असंभव होगा। इसलिए जरूरी है कि रोड शो के स्थान पर रोड सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की मांग सत्ताधारियों का कालर पकड़कर की जाए। बाकी टोल बूथों पर लुटना शाइनिंग-स्मार्ट इंडिया में जनता की किस्मत में सात जन्मों के लिए तो लिखा ही जा चुका है।

इलाज का ड्रामा कर मर्ज से पल्ला झाड़ते नितिन गडकरी

जनवरी से अप्रैल तक हरियाणा में 3964 सड़क हादसों में 1791 लोगो की मौत हो चुकी है। इन हादसों में 17 से 44 वर्ष के मरने वालों की संख्या लगभग 60 फीसदी है। 45 साल से अधिक के 35 फीसदी लोग अपनी जान सड़क हादसों में गवां बैठे हैं।

प्रदेश में हाइवे पर ट्रक, टेम्पो, और ट्रेक्टर से सबसे अधिक 35 प्रतिशत हादसे हुए हैं जिसमें 37 प्रतिशत लोगो कि मृत्यु हुई। ऑटो और दोपहिया से 23 प्रतिशत लोगों की सड़क दुर्घटना में जान जाती रही है। यानी हर तरह के साधन और उम्र के लोग इन हादसों में अपनी जान गँवाते हैं। पर सरकारी तंत्र सिर्फ लाशें गिन कर उनको रिकॉर्ड में लिख लेता है।

सड़क हादसों पर काबू पाने के नाम पर 7 जून से ट्रैफिक और हाईवे पुलिस के साथ परिवहन विभाग मिल कर नया कदम उठाने जा रहा है। सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम तकनीकी विश्वविद्यालय में सड़क सुरक्षा के लिए नागरिक दायित्व विषय पर पंचायत का आयोजन होगा। इसमें प्रशासन ये जानने की कोशिश करेगा कि हादसों के क्या कारण रहे? उनका समाधान क्यों नहीं हुआ और कैसे किया जाए?

ऐसी पंचायतें बारी-बारी से राज्य के अलग-अलग इलाकों में आयोजित की जाएंगी। डी आई जी ट्रैफिक एंड हाइवे, हरियाणा के अनुसार हादसों में कमी लाने के लिए ऐसे आयोजन किये जाएंगे। इसमें सड़क सुरक्षा पर कला प्रदर्शन भी होगा। सोशल मीडिया पर जागरूकता सन्देश फैलाये जाएँगे और ट्रैफिक सम्बन्धी जानकारी दी जाएगी।

इतने प्रयास प्रशासन द्वारा किये जा रहे हैं और इनपर न जाने कितनी धनराशि सरकारी खजाने से उड़ाई जाएगी। पर टेंडर करते समय इतनी सी शर्त नहीं लिख सकते जिसमे हर 500 मीटर पर एक स्वचालित सीढ़ियों वाला पैदल पार पुल बनाया जा सके। बनाने के बाद यही प्रशासन इसका निरीक्षण करे और सड़कों को बेहतर इंजीनीयरिंग से सुरक्षित बनाया जाए। डी आइ जी साहब को ये खबर नहीं शायद कि पुलिस हेल्प लाइन का नंबर कभी लगता ही नहीं जिसमे 100 नंबर भी शामिल है। तो पहले अपना सिस्टम ठीक कर लेते, बजाय पंचायते लगा कर आकाओं को खुश करने के।

सरकारों को सड़क पर दुर्घटना की भेंट चढ़ते नवयुवकों की जरूरत सिर्फ चुनावी रैलियों में है जो पार्टी के झन्डे ले कर मोटरसाइकलों पर बिना हेल्मेट मंत्रियों के पीछे चलें। चुनाव समाप्त होते ही सड़कों पर मरने वाले इन्ही नवयुवकों की सुध सिर्फ पंचायतों और नागरिक कर्तव्यों का हवाला दे कर ली जाती है। जबकि खुद सरकारी तंत्र में रफ्तार के नाम पर टोल बूथों से जनता को लूटा जा रहा है। ये कुछ ऐसा ही है जहाँ सिर्फ मरीज के इलाज की खाना पूर्ति हो रही है पर मर्ज के रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं।

ऑटो में बच्ची का जन्म सरकारी डॉक्टरों की जानलेवा लापरवाही का 'बेहतरीन' नमूना

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 4 जून को ज़िले के नये सीएमओ राजोरा जब कार्यभार सम्भालने के बाद अपने डॉक्टरों व अन्य स्टाफ़ को ढंग से काम करने का प्रवचन दे रहे थे लगभग ठीक उसी समय उनके आधीन पल्ला गांव स्थित पीएचसी (प्राइमरी हैल्थ सेंटर) व बीके अस्पताल के डॉक्टरों ने एक गर्भवती महिला को मौत के हवाले करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी; लेकिन जैसे-तैसे महिला व नवजात बच्ची जिंदा बच गये।

घटना सोमवार सुबह 7 बजे की है। नीतू नामक गर्भवती प्रसव पीड़ा होने पर पल्ला स्थित पीएचसी पहुंची। डॉक्टर की गैरहाजरी में स्टाफ़ ने टालने के अंदाज में महिला के मामले को 'हाई रिस्क' केस बता कर बीके अस्पताल के लिये रैफ़र कर दिया क्योंकि महिला का हिमोग्लोबिन मात्र 7 था।

महिला अपने पति के साथ ऑटो में बैठ कर तुरंत बीके अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टरों के बाहर लम्बी लाइन लगी थी। नम्बर आने पर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कोई 'हाई रिस्क' नहीं है। सब कुछ नार्मल है। इस डॉक्टर ने महिला को प्रसव हेतु अपने यहां दाखिल करने की बजाय वापस पल्ला पीएचसी की ओर रवाना कर दिया। पीएचसी पहुंचने से पूर्व ही महिला को जोरदार प्रसव पीड़ा हुई और शिशु का सिर बाहर आ गया। पति व ऑटो चालक ने जैसे-तेसे हाल-बेहाल महिला को पीएचसी पहुंचाया और प्रसव पूरा हुआ।

जन्म देने वाली यह महिला क्योंकि निर्धन वर्ग से थी इसलिये उसके साथ यह खिलवाड़ किया गया और ज़लील होना पड़ा। यदि वह सम्पन्न होती तो कोई भी नर्सिंग होम उसे प्रसव से 2 दिन पहले ही भर्ती करके उसकी सेवा एवं देख-भाल करता। उधर सरकारी अस्पतालों में हमेशा की तरह घटना के बाद जांच का नाटक शुरू कर दिया गया है जो कुछ समय बाद स्वत: दफ़न हो जायेगा और ऐसी ही किसी अन्य घटना को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो जायेगी।

जनता से उनकी समस्यायें पूछने वाले मंत्री गोयल व अन्य सरकारी नेताओं को आये दिन होने वाली ये सब घटनायें नज़र ही नहीं आतीं। इन नेताओं का काम **'बेटी बचाओ बेटी पढाओ'** का नारा मात्र देने से चल जाता है।

भ्रष्ट सीएमओ गुलशन अरोड़ा को मनचाहे तबादले का इनाम

फ़रीदाबाद (म.मो.) करीब पौने चार साल तक यहां लूट मचाने के बाद गत सप्ताह गुलशन अरोड़ा को गुड़गांव का सीएमओ तैनात कर दिया गया है। विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि फ़रीदाबाद से पहले गुलशन नारनौल में सीएमओ था। इसका घर गुड़गांव में है। नारनौल में वैसे भी लूट कमाई का मामला न के बराबर ही होता है। ऐसे में गुलशन ने तत्कालीन कांग्रेसी स्वास्थ्य मंत्री राव नरेन्द्र से जुगाड़ लगाकर गुड़गांव आने के लिये बहुत ज़ोर लगाये। राव नरेन्द्र ने एक लाख का नज़राना लेकर गुड़गांव तो नहीं दिया, फ़रीदाबाद दे दिया। चलो नारनौल से तो फ़रीदाबाद ही भला था।

गुलशन की यहां पूरी तैनाती के दौरान कोई दिन ऐसा नहीं गया जब उसके खिलाफ़ खबरें न छपी हों, बीके अस्पताल में अफ़रा-तफ़री न रही हो। आये दिन शिकायतों के बावजूद गुलशन की सेहत पर कतई कोई आंच नहीं आई। इसके पीछे स्थानीय विधायकों खासकर सीमा त्रिखा व भाजपाई स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का हाथ था। इसी सुरक्षा कवच के चलते गुलशन ने पौने चार साल यहां बेधड़क लूट मचाई।

ऐसा भी नहीं है कि वह केवल राजनेताओं के बूते लूट कमाई करता रहा। उसने अपने विभागीय अधिकारियों को भी सेट कर रखा था। सेटिंग कैसे होती है, किस को क्या और कैसे देना होता है, यह गुलशन से बेहतर कोई नहीं जानता। अपनी इसी समझ के बूते गुलशन ने अब अपनी मनचाही तैनाती के रूप में गुड़गांव पा लिया है।

बीके अस्पताल: हम नहीं सुधरेंगे, तीन दिन में दूसरी प्रसूति वारदात

4 जून की वारदात को लेकर होने वाली जांच का ड्रामा अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि 6 जून को दूसरी वारदात कर डाली। इस बार हसनपुर के एक गांव से 25 वर्षीय गर्भवती इमराना प्रसव हेतु पलवल के सिविल अस्पताल पहुंची तो हरामखोर डॉक्टरों ने उसे बीके अस्पताल की ओर धकेल दिया। यहां बैठे डॉक्टर उनसे भी बड़े हरामखोर व रिश्वतखोर निकले। उन्होंने केस को अति गंभीर बताते हुये दिल्ली स्थित सफ़दरजंग अस्पताल ले जाने की सलाह जबानी दे डाली, यानी किसी काग़ज पर लिख कर रैफ़र करने की भी जरूरत नहीं समझी। जबानी रैफ़र इस लिये भी किया जाता है ताकि ये हरामखोर कह सकें कि मरीज तो उनके पास आई ही नहीं, अपने आप से सीधे दिल्ली चली गयी।

लेकिन यह ग़रीब मरीज़ किसी तरह भी दिल्ली तक जाने की हैसियत नहीं रखती थी; लिहाजा अपनी सास के साथ अस्पताल के पार्क में ही बैठ गयी और कुछ देर बाद वहीं पार्क में ही एक बच्ची को जन्म दे दिया। अस्पताल के हरामखोरों को जब इसकी सूचना मिली तो वे जच्चा-बच्चा को तुरन्त अंदर ले गये। घंटे-दो घंटे बाद उन्हें एम्बूलेंस में डाल कर उनके गांव भिजवा दिया। वहां वे मरें या जीयें इनकी बला से। अपने को बचाने के लिये इन रिश्वतखोर हरामखोरों ने अनपढ सास-बहू से यह भी लिखवा लिया कि वे यहां दाखिल नहीं होना चाहते, घर जाना चाहते हैं।

ऐसा भी नहीं है कि सरकारी नौकरी में रह कर लूट मचा रहे ये हरामखोर सुधर नहीं सकते; ये तो एक मिनट में सुधर जायें यदि सरकार की अपनी नीयत ठीक हो। शहर में बैठे राजनेताओं की नीयत ठीक हो, स्वास्थ्य विभाग में ऊपर तक बैठे अफ़सरों की नीयत ठीक हो। यह नीयत तभी ठीक हो सकती है जब ये सब इन हरामखोरों द्वारा की जा रही लूट में से हिस्सा न बंटाते हो। अकेले प्रसूति विभाग में करोड़ों की लूट का खेल किसी से छिपा नहीं है।

यदि ऊंचे पायदानों पर बैठे उक्त शासक प्रशासक लूट में से हिससा नहीं बंटा रहे हैं तो क्यों नहीं पल्ला पीएचसी, सम्बन्धित डॉक्टरों के विरुद्ध मरीज़ों की हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराते?

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06